Research Paper

E-ISSN NO : 2455-295X | IMPACT FACTOR VALUE : 5.983
VOLUME : 11 | ISSUE : 1 | SPECIAL ISSUE JANUARY-2025

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा: एक आर्थिक अध्ययन

डॉ. पारस जैन	सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), उदयपुर.
किरण जोशी	शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर.

ABSTRACT:

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। चूंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है, इसलिए जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, और सामाजिक-आर्थिक विषमताएं खाद्य सुरक्षा की जटिलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

शोध में मिश्रित विधियों का उपयोग किया गया है, जिसमें सरकारी स्रोतों से प्राप्त मात्रात्मक डेटा और स्थानीय किसानों तथा समुदाय के नेताओं से प्राप्त गुणात्मक जानकारी शामिल है। निष्कर्षों से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषि सब्सिडी जैसी पहलों ने भूखमरी को कम किया है, फिर भी बुनियादी ढांचे की कमी, बाजार तक पहुंच, और पोषण गुणवत्ता जैसी प्रणालीगत समस्याएं बनी हुई हैं।

यह शोध पत्र जनसंख्या के कमजोर वर्ग के बीच सहनशीलता बढ़ाने, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने, और पोषणयुक्त खाद्य तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वितरण तंत्र में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी स्तरों पर प्रयास शामिल हों।

KEYWORDS:

खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि सब्सिडी, टिकाऊ कृषि ।

परिचय (Introduction):

खाद्य सुरक्षा से आशय राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को समय पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धि से है जिससे वो अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जी सकें। इस हेतु यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक सदस्य की दैनिक पौषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें। देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि भोजन की पर्याप्त उपलब्धता हो एवं सभी लोगो तक इसकी पहुँच हो। भोजन ऐसा हो कि उससे जनसामान्य को पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सके एवं खाद्य सुरक्षा की स्थिरता सुनिश्चित होनी चाहिए।

खाद्य सुरक्षा किसी भी विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। पर्याप्त पोषण नहीं मिलने पर लोग बीमार पडते है एवं समाज में कुपोषण फैलने से शारीरीक एवं मानसिक बाधाएं उत्पन्न होती है। खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता से जनसामान्य की उत्पादकता बढती है एवं आर्थिक विकास को बढावा मिलता है। राष्ट्र में शान्ति एवं स्थिरता को बढावा प्राप्त होता है एवं इससे निर्धनता के कुचक्र से मुक्ति मिलती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने से मानव अधिकारों का पोषण होता है एवं प्रत्येक नागरिक सम्मान से जीवन यापन कर सकता है। स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा विकसित समाज हेतु अति आवश्यक है एवं इसके सुनिश्चितिकरण से आर्थिक विकास को बढावा मिलता है।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वर्ष का सबसे बडा राज्य है जो अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियो के कारण खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। मरूस्थल एंव वर्षा के अभाव के कारण कृषि उत्पादन कम रहता है। सामान्यतया यहां मोटे अनाज बोए जाते है जिनसे पर्याप्त पोषण की प्राप्ति नहीं होती है। वर्षा के अभाव में एक से अधिक फसले लेना सम्भव नहीं हो पाता है।

गरीबी एवं बेरोजगारी का स्तर राजस्थान में व्याप्त है जिससे क्रय क्षमता के अभाव में जनसामान्य कुपोषण का शिकार हो जाते है तथा महिलाओं में कुपोषण से भावी पीढी में मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का सही विकास नहीं हो पाता है। परिवहन व भण्डारण की अपर्याप्त सुविधाओं ने खाद्य सुरक्षा की समस्या को व्याप्त बना दिया है एंव प्राकृतिक प्रकोपो के कारण राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति दयनीय है।

प्रस्तुत शोध पत्र में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सन्दर्भ साहित्य का अवलोकन (Review of Literature):

शोधकत्ता ने शोध विषय से संबंधित विभिन्न शोध अध्ययनों का विश्लेषण किया एवं कुछ मुख्य शोध अध्ययनों का सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

Payne, Hannah E. & Gray, Bobbi & Davis, Siena F. & Hine, Cassidy A. & Das, Arindam & Kabra, Manisha & Crookston, Benjamin T., 2016. [1] में बताया कि भारत में खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के बीच। इस अध्ययन का उद्देश्य राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को मापना और संबंधित कारकों का वर्णन करना है। इस अध्ययन के लिए स्वयं सहायता समूहों से संबंधित गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की माताओं का सर्वेक्षण किया गया। महिलाओं और बच्चों के बीच खाद्य असुरक्षा से जुड़े कारकों में बढ़ती गरीबी, कम आहार विविधता, जनजाति से संबंधित होना, और भोजन खर्च को कवर करने के लिए पैसे बचाने में असमर्थता शामिल थे। महिलाओं के लिए, अधिक सामना करने की रणनीतियों का उपयोग करना और पति द्वारा महिला की कमाई के पैसे के उपयोग पर निर्णय लेना खाद्य असुरक्षा से जुड़े थे, जबकि बच्चों में, आंगनवाड़ी केंद्र से भोजन प्राप्त न करना खाद्य असुरक्षा से संबंधित था। ये निष्कर्ष सुझाव देते हैं कि खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कदमों में भोजन आवश्यकताओं के लिए बचत को सुविधाजनक बनाना, महिलाओं के निर्णय लेने की शक्ति में सुधार करना, और बाल विकास आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संगठनों के साथ संबंध बढ़ाना शामिल हो सकता है।

Mai, Nhat Chi, 2022. [2] ने राजस्थान, भारत के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति और इसके विभिन्न घटकों जैसे कि खाद्य उपलब्धता, पहुंच और स्थिरता का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में संकेतक आधारित दृष्टिकोण के आधार पर एक बहुआयामी सूचकांक का उपयोग किया गया है। जिलों को निम्न, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए फळे मैपिंग कंप्यूटर अनुप्रयोग और क्विंटाइल विधि का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और इसके संबंधित घटकों के महत्वपूर्ण निर्धारकों का पता लगाने के लिए बहु-प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग किया गया।

परिणाम बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा और इसके घटकों (उपलब्धता, पहुंच, और स्थिरता) के संदर्भ में जिलों के बीच व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। पाया गया कि राजस्थान राज्य में गंगानगर जिला (0.407) खाद्य स्थिरता (0.401) के कारण सबसे अधिक खाद्य-सुरक्षित

जिला माना गया। इसके विपरीत, डूंगरपुर जिले में सबसे कम खाद्य उपलब्धता (0.084) और पहुंच (0.183) के कारण खाद्य सुरक्षा का स्तर सबसे निम्न पाया गया। इसके अलावा, सूखे क्षेत्रों से संबंधित जिले सतही सिंचाई सुविधाओं वाले जिलों की तुलना में अधिक संवेदनशील और अपेक्षाकृत कम खाद्य-सुरक्षित हैं।

Gupta, Eshita (2019):[3] ने राजस्थान के छह जिलों के 414 ग्रामीण किसानों के नमूने के साथ अंतर में अंतर दृष्टिकोण का उपयोग किया। अध्ययन से पता चलता है कि सोलर वाटर पंप के अपनाने से ऊर्जा-पानी-खाद्य नेक्सस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जयपुर और सीकर जिलों में सोलर पंप अपनाने वालों द्वारा औसत भूजल खपत में 16-39: की वृद्धि हुई है जयपुर और सीकर में बिजली की औसत खपत में 1-17: की कमी और श्रीगंगानगर में 17-134: की कमी हुई हैय बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ में औसत डीजल खपत में 50-106: की कमी आई है। खाद्य सुरक्षा में भी सुधार हुआ है, जैसा कि जयपुर और सीकर में औसत फसल गहनता में 2-10: और बीकानेर में 2-9 की वृद्धि से स्पष्ट है। जयपुर में फलों और सब्जियों के अंतर्गत सकल फसल क्षेत्र में 12-53 और बीकानेर में 10-116 की वृद्धि हुई है। आय सुरक्षा में भी सुधार हुआ है, सोलर पंप अपनाने वालों के वार्षिक लाभ में जयपुर और सीकर में 3.1-41.5 और डीजल उपयोग वाले जिलों में 14-76 की वृद्धि देखी गई है।

Kumar, Shalander & Upadhyay, A.D., 2009. [4] ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पानी की कमी और बदलते संसाधन स्थितियों के तहत बकरियों के पालनहारों की अनुकूलन रणनीति का विश्लेषण किया गया है। इनपुट-आउटपुट मॉडल का उपयोग खेती प्रणालियों के विभिन्न घटकों के बीच संबंधों की मात्रा को मापने के लिए किया गया है। यह अध्ययन 2004-2005 के वर्ष के लिए नागौर जिले से यादृच्छिक रूप से चयनित 60 बकरियां रखने वाले और 25 ऐसे कृषि से प्राथमिक डेटा पर आधारित है, जिनके पास बकरियां नहीं हैं। ट्रांसह्यूमन्स सिस्टम को अपनाने के बजाय, किसानों को एक नवाचारपूर्ण कृषि प्रणाली विकसित करते हुए पाया गया है, जिसने न केवल उनके परिवार के लिए अनाज का सतत उत्पादन किया, बल्कि उनके छोटे रुमिनेंट्स के लिए चारा और घास भी सुनिश्चित किया। तीन प्रकार की कृषि प्रणालियाँ वर्षा-आधारित बकरी आधारित कृषि प्रणाली, आंशिक रूप से सिंचित बकरी आधारित कृषि प्रणाली, और वर्षा-आधारित फसल आधारित कृषि प्रणाली, का किया गया है। उभरती संसाधन और पर्यावरणीय परिस्थितियों के उत्तर में, बकरी पालनहारों ने कृषि प्रणाली के विभिन्न घटकों के बीच मौजूद संभावित सहक्रियाओं का उपयोग किया है। हालांकि, मौजूदा बकरी उत्पादन को आधुनिक बकरी पालन प्रथाओं के साथ बेहतर तरीके से समायोजित करने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा अपने कुछ खेतों को बकरियों और भेड़ों को सूखा मौसम में चराने के लिए छोड़ने का नवाचारपूर्ण विचार, एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसानों को इस खाली भूमि को अनुशंसित दलहनी और गैर-दलहनी घासों के साथ चरागाह के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह मॉडल अन्य समान शुष्क क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।

शोध के उद्धेश्य (**Objectives of Study**):

1. राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन के स्तर को ज्ञात करना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति का अध्ययन करना।

2. उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को आकंलित करना।

शोध प्रविधि (**Research Methodology**):

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रविधि निम्नवत् है:

खाद्य सुरक्षा एक अत्यन्त गंभीर विषय है। यदि किसी राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो उस देश का विकास बेमानी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत शोध के लिए राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले का अध्ययन हेतु चयन किया गया है। उदयपुर जिला एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां अधिकांश जनसंख्या जनजातिय है एवं पहाडी क्षेत्रों में निवासरत है। ये अपने जीवन यापन हेतु कृषि कार्यो पर निर्भर है परन्तु मानसून की अस्थिरता एंव सिंचाई के अभाव में कृषि उत्पादन में भारी उतार-चढाव देखने को मिलते है। अधिकांश जनसामान्य को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः प्रस्तुत शोध में इस तथ्य को ज्ञात करने हेतु उदयपुर जिले का चयन किया गया है।

सुक्ष्म अध्ययन हेतु उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील के यादृच्छिक रूप से चयनित 5 गांवों के 50 व्यक्तियों से (प्रत्येक गांव से 10 व्यक्ति) खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की गयी है।

प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकडों पर आधारित है। प्राथमिक आंकडे उत्तरदाताओं के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त किए गए है वही द्वितीयक आंकडे आयोजना विभाग एंव खाद्य विभाग से प्राप्त किए गए है। संकलित आंकडों को विभिन्न सांख्यिकी उपकरण यथा औसत, प्रतिशत, प्रभाव विचलन से विश्लेषित किया गया है।

निष्कर्ष एंव विवेचन (**Results & discussion**):

खाद्य सुरक्षा की सुनिष्चितता काफी हद तक खाद्यान्न उत्पादन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संरचना पर निर्भर करती है। अग्र तालिका में राजस्थान में विभिन्न वर्षो में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1: खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्रफल एंव उत्पादन का विवरण

वर्ष	खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्रफल			खाद्यान्न उत्पादन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
2004-05	8805767	3273385	12079152	5196251	6966958	12163208
2005-06	9078419	3452365	12530784	3958805	6864824	10823629
2006-07	8879867	3853472	12733339	5650933	9277384	14928317
2007-08	9536970	4107111	13644081	7816354	8268081	16084435
2008-09	9368836	3870266	13239102	7518851	9175000	16693851
2009-10	9694321	3538627	13232948	3669341	8690498	12359839
2010-11	10456402	5201947	15658349	10565096	13009017	23574113
2011-12	9747839	4692230	14440069	9935018	11990146	21925164
2012-13	7750711	4660920	12411631	7015876	13044250	20060126
2013-14	8332204	5492979	13825183	7057431	13662061	20719492
2014-15	7891053	4987828	12878881	7867338	11776218	19643556
2015-16	8612842	4404393	13017235	6139453	12147574	18287027
2016-17	10003310	5274062	15277372	8256255	14883585	23139840
2017-18	10089370	4947309	15036679	8147746	13957321	22105067
2018-19	10141042	4857332	14998374	8489550	14670512	23160062
2019-20	9886011	6299241	16185252	8955556	17679662	26635218
2020-21	10130788	5421238	15552026	11690796	15633655	27324451
2021-22 (अ.सं.)	10225774	5376006	15601780	8621867	14569970	23191837
2022-23 (अ.)	9974827	5318103	1592930	10959629	14320174	25279803

स्रोत: आर्थिक समीक्षा 2023-24

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2004-05 में खाद्यान्नों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 12079152 हैक्टेयर था जो वर्ष 2022-23 में बढकर 15292930 हैक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि 26.60 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 12163209 मै. टन था जो 2022-23 में बढकर 25279803 मै. टन हो गया है। यह वृद्धि 107.83 प्रतिशत रही है। स्पष्ट है कि खाद्यान्नों के अधीन क्षेत्रफल एंव कुल खाद्यान्न उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

अग्र तालिका में विगत 4 वर्षो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं के आवंटन का उठाव का विवरण प्रस्तुत दिया गया है:

तालिका 2: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत गेहूं का आवंटन एवं उठाव

(मात्रा मै.टन में)

क्र.स.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1.	2019-20	2685838.18	2635723.84	98.13%
2.	2020-21	2754125.914	2747337.621	99.75%
3.	2021-22	2883344.396	2545851.303	98.55%
4.	2022-23	2645921.761	2604685.407	98.44%

स्रोत: खाद्य विभाग, राजस्थान

तालिका से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं के उठाव का प्रतिशत लगभग 98 प्रतिशत रहा है जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम है।

सुक्ष्म अध्ययन हेतु प्रतिदर्श में सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र के 50 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया जिसके निष्कर्ष अग्र तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 3: उदयपुर जिले में खाद्य सुरक्षा की स्थिति

गांव	उचित मुल्य की दुकान समय पर खुलती है		खाद्यान्न की उपलब्धता		विद्यालय में बच्चों को भोजन प्राप्त होता है		घर पर सभी को पर्याप्त एवं पोष्टिक भोजन की उपलब्धता	
	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
अमरपुरा	5	5	4	6	10	-	3	7
मोर डूंगरी	4	6	5	5	10	-	5	5
चैकडिया	7	3	5	5	10	-	4	6
सरू	5	5	6	4	10	-	5	5
जाबला	6	4	7	3	10	-	4	6
योग	27	23	27	23	10	-	21	29

स्रोतः क्षेत्र सर्वेक्षण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि उनके क्षेत्र में उचित मुल्य की दुकान समय पर खुलती है वही शेष 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उचित मुल्य की दुकान समय पर नहीं खुलती है।

अध्ययन क्षेत्र के 54 प्रतिशत उत्तरदाता मानते थे कि उचित मुल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त थी वही शेष 46 प्रतिशत उत्तरदाता इसके विरूद्ध थें।

अध्ययन क्षेत्र के समस्त 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि विद्यालय में बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध हो रहा था कि विद्यालय में बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध हो रहा था। अध्ययन क्षेत्र के 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि उनके घर पर सभी को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो रहा था वही शेष 58 प्रतिशत उत्तरदाता मानते थे कि उनके घर पर सभी को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा था।

निष्कर्ष (Conclusions):

1. राजस्थान में खाद्यान्नों के अधीन भुमि का क्षेत्रफल एंव खाद्यान्नों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है परन्तु अभी भी खाद्य सुरक्षा की पुर्ण सुनिश्चितता नहीं हो पायी है।

2. उचित मुल्य की कई दुकाने समय पर नहीं खुलती है जिससे आम आदमी को समस्या पैदा होती है। एंव खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चितीकरण में बाधा आती है।

3. वर्तमान में जनजातिय क्षेत्रों में परिवारों के सभी सदस्यों को पर्याप्त एंव पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है।

सुझाव (Suggestions):

राजस्थान राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है:

1. कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का प्रसार किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति, फव्वारा प्रणाली इत्यादि के उपयोग को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

2. मरू प्रदेश में कम पानी में पैदा होने वाली फसलों को उगाने के प्रयास करने चाहिए। जैसे खजूर इत्यादि।

3. गरीबी एंव बेरोजगारी को पूर्णतया समाप्त करने हेतु विशेष रणनीति निर्मित कर इसका सम्पूर्ण खात्मा किया जाना चाहिए।

4. परिवहन की सुविधाओं का विस्तार किया जाना अति आवश्यक है जिससे खाद्यान्न की सर्वत्र उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें।

5. सरकार को भण्डारण सुविधाओं का व्यापक प्रसार करना चाहिए।

REFERENCES

1. Christopher, Anita & Nyugen, Phuong & Singh, Sudhir K. & Sarwal, Rakesh & Bhatia, Neena & Johnston, Robert & Joe, William & Sarswat, Esha & Menon, Purnima & Nguyen, Phuong Hong, 2022. "State nutrition profile: Rajasthan," POSHAN data notes 82, International Food Policy Research Institute (IFPRI).

2. Swain, Mrutyunjay & Sharma, Shreekant, 2015. "Impact of MNREGA on Employment of Disadvantaged Groups, Wage Rates and Migration in Rajasthan," Indian Journal of Agricultural Economics, Indian Society of Agricultural Economics, vol. 70(3), pages 1-15.

3. Ilse Köhler-Rollefson & Hanwant Singh Rathore, 2021. "The Case of the Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary and Camel Pastoralism in Rajasthan (India)," Sustainability, MDPI, vol. 13(24), pages 1-9, December.

4. Dhaka, Surjeet Singh & Urmila & Poolsingh, Dharavath, 2023. "Comparative Analysis of Price Forecasting Models for Garlic (Allium sativum L.) in Kota District of Rajasthan, India," Research on World Agricultural Economy, Nan Yang Academy of Sciences Pte Ltd (NASS), vol. 4(4), October.

5. Saini, Shweta & Sharma, Sameedh & Gulati, Ashok & Hussain, Siraj & von Braun, Joachim, 2017. "Indian food and welfare schemes: Scope for digitization towards cash transfers," Discussion Papers 261791, University of Bonn, Center for Development Research (ZEF).

6. Singh, Vivek Kumar & Singh, RD, 2007. "Agricultural development and regional carrying capacity measurement of agro-ecosystem in Jhabua tribal district in Madhya Pradesh," MPRA Paper 30565, University Library of Munich, Germany, revised Mar 2007.

7. Payne, Hannah E. & Gray, Bobbi & Davis, Siena F. & Hine, Cassidy A. & Das, Arindam & Kabra, Manisha & Crookston, Benjamin T., 2016. "Factors associated with food insecurity among women and children in rural Rajasthan, India," Journal of Gender, Agriculture and Food Security (Agri-Gender), Africa Centre for Gender, Social Research and Impact Assessment, vol. 1(3)

8. Mai, Nhat Chi, 2022. "Measuring and Mapping Food Security Status of Rajasthan, India: A District-Level Analysis," OSF Preprints d2buh, Center for Open Science.

9. Gupta, Eshita (2019): The impact of solar water pumps on energy-water-food nexus: Evidence from Rajasthan, India

10. Kumar, Shalander & Upadhyay, A.D., 2009. "Goat Farmers' Coping Strategy for Sustainable Livelihood Security in Arid Rajasthan: An Empirical Analysis," Agricultural Economics Research Review, Agricultural Economics Research Association (India), vol. 22(2), July.

11. Kumar, Shalander & Upadhyay, A.D., 2009. "Goat Farmers' Coping Strategy for Sustainable Livelihood Security in Arid Rajasthan: An Empirical Analysis," Agricultural Economics Research Review, Agricultural Economics Research Association (India), vol. 22(2).